

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220552  
SG-DL-E-16072020-220552

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2020/आषाढ़ 25, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं.68
No. 132]	DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2020/ASHADHA 25, 1942	[N.C.T.D. No. 68

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÜk ½k Lo&1½foHkx

v f/H þuk

दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

I a 72@2019&j kT; d j

I aÜk 3½18½foÜk½k Lo&I½@2020&21@Mh I &IV@29&राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ

अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतियुत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
सुनील सहगल, उप सचिव-I V (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th July, 2020

**No 72/2019- State Tax**

**No. F. 3(18)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/29.**—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)